



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220274
CG-DL-E-30062020-220274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942

No. 159]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

(प्रकरण सं. सीवीडी-ओआई-04/2020)

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "7 मिमि. व्यास से अधिक एल्युमिनियम वायर/वायर रॉड्स" के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/3/2020-डीजीटीआर.—

1. वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तु की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है जिसमें मलेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "7 मिमि. व्यास से अधिक एल्युमिनियम वायर/वायर रॉड्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "7 मिमि. व्यास से अधिक एल्युमिनियम वायर/वायर रॉड्स" हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु के तार / वायर रॉड दोनों शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री एल्यूमिना है। विचाराधीन उत्पाद को एल्यूमिना के स्मेल्टिंग से उत्पादित और उससे प्राप्त प्राथमिक एल्यूमिनियम गर्म धातु की कॉस्टिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। वायर/वायर रॉड की उत्पत्ति भी स्क्रैप के पिघलने से भी हो सकती है। स्क्रैप के माध्यम से उत्पादित वायर रॉड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे है। विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक रूप से विद्युत उद्योग, इस्पात उद्योग और अन्य में प्रयोग होता है।

4. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 76 के सीमाशुल्क शीर्ष 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100 और 76052100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

6. यह आवेदन वेदांता लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं। आवेदकों ने कहा है कि वेदांता लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के एक आयातक नामतः स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एसपीटीएल) से संबंधित है। तथापि, एसपीटीएल ने संबद्ध देश से जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

7. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक के उत्पादन का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. कथित सब्सिडीकरण का आधार

8. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/ निर्यातक संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं जिनमें उन प्रदशों और जिलों की सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं जहां ये उत्पादक/निर्यातक अवस्थित हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडियों/कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है :

I. अनुदानों के रूप में अभिज्ञात स्कीम

कार्यक्रम संख्या 1: बाजार विकास अनुदान

कार्यक्रम संख्या 2: व्यवसाय/ उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार

II. निर्यात ऋण तथा निर्यात वित्त पोषण के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 3: निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण

कार्यक्रम संख्या 4: क्रेता ऋण गारंटी

III. कर प्रोत्साहनों के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 5: पायोनियर का दर्जा

कार्यक्रम संख्या 6: निवेश कर नीतियां

कार्यक्रम संख्या 7: पुननिर्देश भत्ता

कार्यक्रम संख्या 8: त्वरित पूंजी भत्ता

कार्यक्रम संख्या 9: समूह राहत

कार्यक्रम संख्या 10: टैरिफ संबंधी प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 11: औद्योगिक भवन भत्ता/ औद्योगिक भवन निर्माण भत्ता (आई बी ए)

कार्यक्रम संख्या 12: संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता

कार्यक्रम संख्या 13: निर्यातों के संवर्धन हेतु दुगुनी कटौती

कार्यक्रम संख्या 14: विनिर्माण और पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे में सेवाओं संबंधित निर्माण हेतु प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 15: आयात शुल्क बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्राँ बैक

कार्यक्रम संख्या 16: आउट सोर्सिंग विनिर्माण कार्यकलापों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम संख्या 17: मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम संख्या 18: कच्ची सामग्री/ घटकों पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम संख्या 19: निर्यात संवर्धन हेतु दुगुनी कटौती

कार्यक्रम संख्या 20: निर्यात कार्गो के संवर्धन हेतु दुगुनी कटौती

कार्यक्रम संख्या 21: बढ़े हुए निर्यात हेतु भत्ता

कार्यक्रम संख्या 22: मुक्त व्यापार जोनों में निर्यातकों हेतु कर छूट

IV. पर्याप्त से कम मूल्य के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 23: भूमि और विद्युत के लिए पर्याप्त से कम भुगतान

निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो जांच के दौरान, विषय वस्तुओं के उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा मौजूद और प्राप्त किया जा सकता है।

ड. परामर्श

10. दिनांक 29 जून, 2020 को सलाह परामर्श हुआ और उसमें मलेशिया सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। मलेशिया सरकार ने कतिपय कार्यक्रमों के अस्तित्व/प्रयोज्यता से इंकार करते हुए तथा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक द्वारा कुछ कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने और कुछ कार्यक्रमों में नगण्य निवल प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के बारे में बताया। तदनुसार, कार्यक्रम सं. 14, 20 और 22 को जांच के दायरे से बाहर किया गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि अन्य कथित कार्यक्रमों की मौजूदगी, उनकी प्रतिसंतुलनीयता और उनमें प्राप्त लाभ की मात्रा का विश्लेषण करना संगत नियमावली के अनुसार एक जांच के माध्यम से अपेक्षित है।

च. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

11. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के चलते कथित सब्सिडीकरण तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और न्यूनकारी प्रभाव की दृष्टि से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत

किए हैं। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में संबद्ध देशों से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के कारण हो रही है जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

छ. सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत

12. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित उल्लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सत्य सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कार्यक्रम सं. 14, 20 और 22 के अलावा तथा नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा इस जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश मलेशिया है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 (9 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि को आयातों में वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट, घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अवधि के दौरान वर्तमान मामले के तथ्यों में उचित समझा गया है।

ञ. प्रक्रिया

15. नियमावली के नियम 7 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

16. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

17. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ठ. समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियमावली के नियम 7 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ण. असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2020

(Case No. CVD OI-04/2020)

Subject : Initiation of anti-subsidy investigation concerning imports of “Aluminium Wire /Wire Rods above 7 mm dia”, originating in or exported from Malaysia.

F. No. 6/3/2020-DGTR.—

1. Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for anti-subsidy investigation concerning imports of “Aluminium “Wire/Wire Rods above 7 mm dia” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The applicants have alleged that the material injury to the Domestic Industry is being caused due to subsidized imports from the subject country and have requested for imposition of countervailing duty on imports of subsidized subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Aluminium “Wire/Wire Rods above 7 mm dia”. The scope of the product under consideration includes both alloyed and non alloyed wire/wire rods. The major raw material used for manufacturing the product under consideration is alumina. The product under consideration is produced and obtained by casting primary aluminium hot metal obtained from smelting of alumina. Wire/ Wire rods can also be produced by melting of scrap. Wire rod produced through scrap is beyond the scope of the product under consideration.
4. The product under consideration is primarily used in electrical industry, steel industry and others. The product is classified under the Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs heading 76011040, 76012040, 76041010, 76042920, 76051100, and 76052100. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation.

B. Like Article

5. The applicants have claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic industry

6. The Application has been jointly filed by Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited. The Applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country. The applicants have stated that Vedanta Limited is related to one of the importers of product under consideration, namely Sterlite Power Transmission Limited (SPTL). However, the SPTL has not imported the product under consideration during the period of investigation from the subject country.

7. As per evidence available on record, the Applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

D. Basis of Alleged Subsidization

8. The Applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located, and other Public bodies. The applicants have relied upon the relevant laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public bodies as available in the public domain.
9. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

I. Scheme Identified in form of Grants:

Program No.1: The Market Development Grant

Program No. 2: Business/ Industry Excellence Award

II. Schemes Identified in form of Export Credit and Export Financing:

Program No. 3: Export Credit Refinancing

Program No. 4: Buyer Credit Guarantee

III. Schemes Identified in form of Tax Incentives:

Program No. 5: Pioneer Status

Program No. 6: Investment Tax Policies

Program No. 7: Reinvestment Allowance

Program No. 8: Accelerated Capital Allowance

Program No. 9: Group Relief

Program No. 10: Tariff Related Incentives

Program No. 11: Allowance Industrial Building/ Industrial Building Allowance (IBA)

Program No. 12: Allowance for Plants and Machinery

Program No. 13: Double Deduction for promotion of Exports

Program No. 14: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor

Program No. 15: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty

Program No.16: Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities

Program No. 17: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

Program No. 18: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components

Program No. 19: Double Deduction for Promotion of Exports

Program No. 20: Double Deduction for Promotion of Export Cargo

Program No. 21: Allowance for Increased Export

Program No. 22: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

IV. Schemes Identified in form of Provision for Less than Adequate Remuneration:**Program No. 23: Less than Adequate Remuneration for Land & Electricity.**

The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/exporters of the subject goods, during the course of investigation.

E. Consultation

10. Consultation was held on 29th June, 2020 and was attended by the officials of the Government of Malaysia. The Government of Malaysia denied existence/ applicability of certain programs and non-availment of some of the program by producers/exporters of the product under consideration. Accordingly, program nos. 14, 20 and 22 have been taken out from the purview of the investigation. The Authority considers that the existence of other alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analyzed through an investigation as per the relevant Rules.

F. Injury and Causal Link

11. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place due to the alleged subsidization, resulting in increased volume of subsidized imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The performance of the domestic industry has been adversely impacted in respect of production, capacity utilization, sales, profits, return on capital employed and cash flow, as a result of subsidized exports from subject country. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by subsidized exports from the subject country to justify initiation of a countervailing duty investigation.

G. Initiation of Anti-Subsidy Investigation

12. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidization of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidization and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies except those under programs 14, 20 and 22 in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Subject Country

13. The subject country for the present investigation is Malaysia.

I. Period of Investigation (POI)

14. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2019 to December 2019 (9 months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI. The period of investigation proposed by the applicants is considered appropriate in the present case in view of increase in imports, decline in the import price, and consequent adverse effect on the domestic industry during the period.

J. Procedure

15. Principles as given in Rule 7 of the Rules shall be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

16. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in.

17. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl2-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 7(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All interested parties are advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

30. In terms of Rule 7(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Special Secy. & Designated Authority